

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी  
सचिव, वित्त  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक: 24 जनवरी, 2019

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट उपयोग तथा प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों में ई-पेमेंट की प्रणाली लागू रहने के फलस्वरूप आहरण वितरण के कार्य हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

वित्तीय वर्ष के अधीन बजट एवं लेखा सम्बन्धी प्रक्रिया तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-196/XXVII(1)/2015 दि० 24 फरवरी, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित देयकों को कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

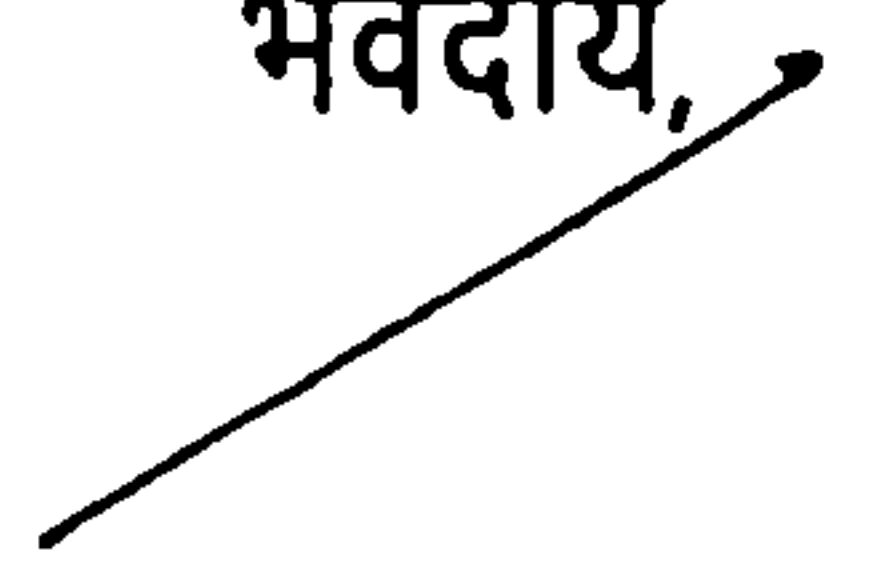
(1) प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर से सभी वित्तीय स्वीकृतियां (केन्द्रपोषित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, एस०पी०ए० तथा एस०पी०ए०आर को छोड़कर) बिलम्बतम् 15.02.2019 तक जारी कर दी जायेंगी।

(2) सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त देयकों को कम्प्यूटर से जनरेट एवं अप्रूव करते हुए बिलम्बतम् रूप से 24 मार्च, 2019 तक मय आई०डी० के भौतिक रूप से देयकों को कोषागार में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। देयकों को आनलाईन तैयार किया जाये, मैनुअल बिलों का पारण कोषागार के द्वारा नहीं किया जायेगा।

(3) कोषागारों/उपकोषागारों में ई-पेमेंट के लिए आहरण वितरण अधिकारियों से उक्तानुसार प्राप्त देयकों की चैकिंग बिलम्बतम् 27 मार्च, 2019 तक आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा ई-पेमेंट के लिए ट्रान्जेक्शन फाइल को बिलम्बतम् दिनांक 29 मार्च, 2019 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय ताकि दिनांक 31 मार्च, 2019 के पूर्व ही ई-ट्रान्जेक्शन की जाँच कर ई-देयकों के भुगतान के सफल अथवा असफल रहने की सही स्थिति ज्ञात हो सके।

(4) राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पार्किंग फण्ड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाय तथा न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखा जाय। इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी प्रशासकीय विभाग अपनी वित्तीय स्वीकृति की समय सारिणी इस प्रकार से बना लें कि सभी स्वीकृतियों के देयकों हेतु कोषागार से प्राप्त चेकों का भुगतान दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

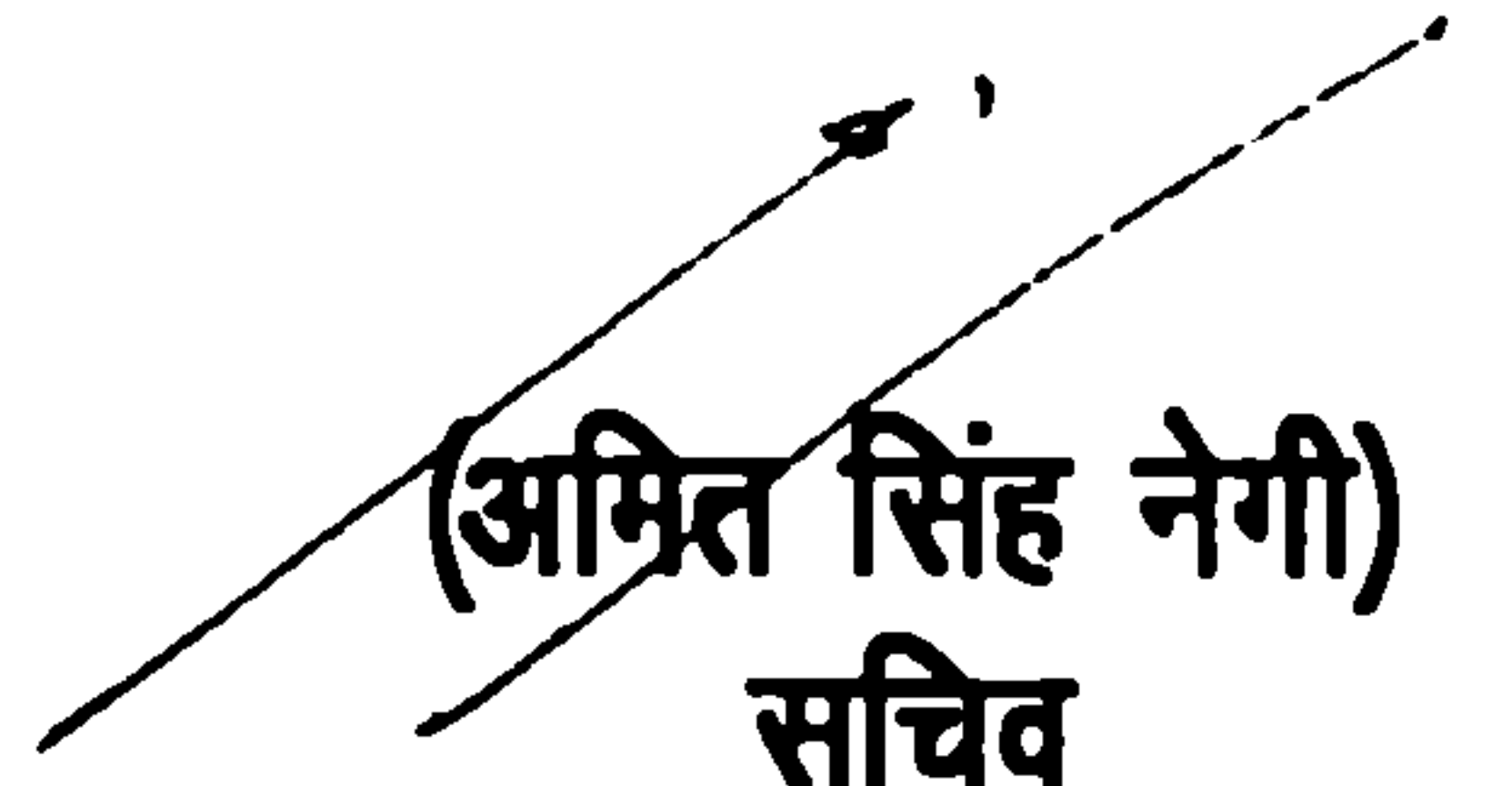
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,  
  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या- 75 /08(150)-2015/XXVII(1)/2019, तददिनांक 24/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, देहरादून।

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव



प्रेषक,

निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला,  
देहरादून।

- सेवा में, 1. अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड  
शिविर कार्यालय, हल्द्वानी  
जनपद-नैनीताल
2. मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।
3. वित्त अधिकारी,  
भुगतान एवं लेखा कार्यालय  
नई दिल्ली।

संख्या 6407/01(2)/सामान्य पत्राचार/विभाग/आयोग/नि0को0पें0ह0/2019 दि006/फरवरी, 2019

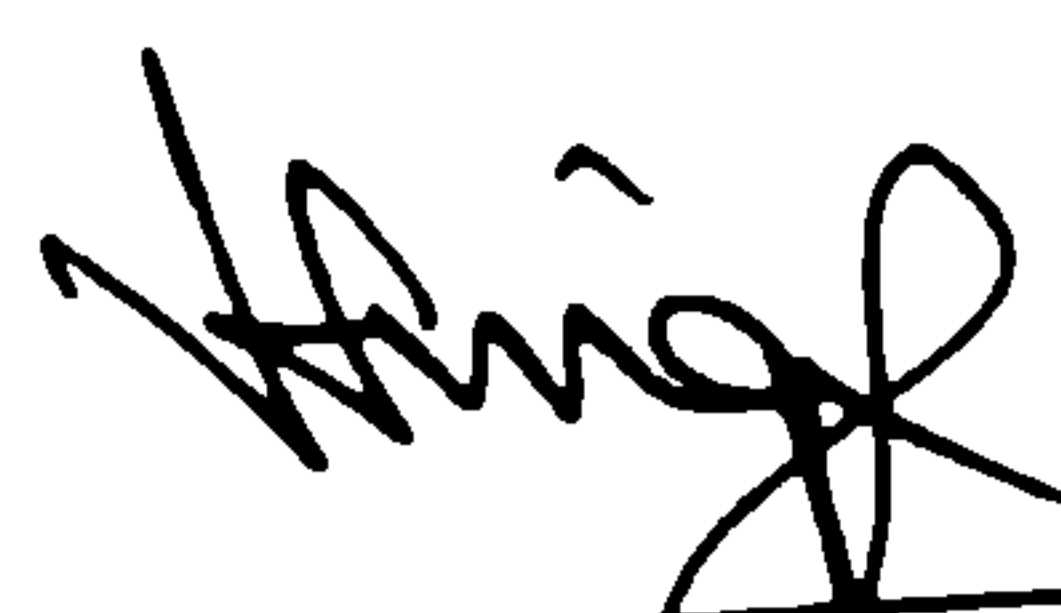
विषय: शासन के शासनादेश संख्या 75/08(150)-2015/XXVII(1)/2019 दि0 24.01.2019 तथा  
कार्यालय ज्ञाप संख्या 14(1)/XXVII(7)/18-30(7)/2016 दि0 21.01.2019 में किये गये  
प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरण/भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या 75/08(150)-2015 /XXVII(1)  
/2019 दि024.01.2019 तथा वित्त अनुभाग-7 कार्यालय ज्ञाप संख्या 14(1)/XXVII(7)/18-  
30(7)/2016 दि0 21.01.2019 की छाया प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं, कि  
वित्तीय वर्ष 2018-19 जो समाप्ति की ओर है, में किये गये प्राविधानों/प्रतिबन्धों एवं दिये गये  
दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आहरण/भुगतान आदि किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही  
सुनिश्चित कर ली जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
जगत सिंह चौहान  
अपर निदेशक,  
कृते निदेशक।